# जल प्रबंधन - एक समस्या एवं समाधान

**प्रा.कु.मंगला माधवराव कनाटे**, भुगोल विभाग प्रमुख, स्व. पंचफुलाबाई पावडे कला, वाणिज्य महिला महाविद्यालय, वरूड.

जल विश्व् की सबसे अधिक उपयोगी, बहुमुल्य तथा सर्वाधिक मात्रा मे उपलब्ध वस्तु है. इस पृथ्वी का तीन चौथाई भाग जल से आप्ल वित है. जल हमे भुमि के नीचे समुद्रो, महासागरो, नदी नाली व झीलो की रूप मे उपलब्ध है. जल मात्रा भुमी पर ही नही, अपितु वायु मंण्डल मे जलबाष्प, धुन्ध, ओस, कोहरा तथा बादलो के रूप मे भी विचरण करता है. भुमिगत स्त्रोतो से जल कुँओ, बावडियो, आदि से तथा भुमि के नीचे से ट्युबवैल आदि से बाहर निकला जाता है.

संपुर्ण भुमण्डल मे 1 अरब, 46 करोड घन किलामिटर, जल उपलब्ध है. इसमे से 93 प्रतिशत जलमहासागरो एवं सागरो 41 प्रतिशत भू - गर्भ मे 2 प्रतिशत जल ध्रुवों तथा ग्लेशियर्स पर जमी बर्फ के रूप मे तथा 0.05 प्रतिशत जल झीलो एंव नदियो मे शुध्द जल संसाधनो के रूप मे उपलब्ध होता है.विश्व मे पीने योग जल की कुल मात्रा 37500 घन किलोमिटर है.

जल जीवन का मुख्य आधार है. साथ ही साथ सभी जीव जंन्तुओ, पदपो व मानवो के. जीवनयापन हेतु यह एक परम आवश्यकता है. तथा इस परम आवश्यकता को प्रकृती ने पृथ्वी पे तीन चौथाई भाग के रूप मे बहुतायत से उपलब्ध करवाया है. किन्तु ऐसा होने पर भी जल के लिए अर्थात पानी के लिए समय समय पर त्राहि त्राहि मच जाती है. तथा जलवर्ष और विश्व जल दिवस मनाये जाते है. कहा जाता है की यदी भविष्य मे कोई विश्व युध्द होगा तो वह जल को लेकर होगा.

हमारे देश मे ग्रामिण पेयजल के क्षेत्र मे चुनौतियो का अंबार लगा है.विश्वभर मे एक अरब से भी अधिक लोगो को सुरक्षित और भरोसेमंद जलस्त्रोत नसीब नही है. जीवन के सभी रूपो की बुनियादी जरूरतो मे पानी सबसे महत्वपुर्ण है और यह देश के समाजिक आर्थिक विकास की कुंजी है.अनुमान है की वर्तमान मे विश्व् 1 अरब 10 करोड आबादी को पीन के पानी ठीक से मयरसर नही है.वर्ष 2050 तक के आकलन से संकेत मिलता है की विश्व की दो तिहाई आबादी का पीने के पानी दिक्कत रहेगी. कुछ को कम हो सकती है तो कुछ ज्यादा पानी की गुणवत्ता को बनाए रखना और दिर्घकालीन आधार पर इसकी उपलब्धता सुनिश्चित करना भारत की प्रमुख चुनौतियो मे सबसे अहम है. औद्योगिक गतिविधियो के कारण जलप्रदुषण की बढती समस्या, जनसंख्या मे वृध्दी और कृषी क्षेत्र के लिए पानी की बढती मांग ने एसी स्थिती उत्पन्न कर दि है की ग्रामिण क्षेत्रो के कुछ भागो मे सुरक्षित पेयजल पहुचाना एक समस्या बन गई है.

**स्त्रोतों का न्यायोचित प्रबंन्ध :** जलस्त्रोतों के न्यायोचित विदोहन एवं समान वितरण हेतु पहली राष्ट्रीय जल नीती सन 1987 मे स्वीकार की गई. इस निती पर चलाते हुये भी जलस्त्रोतों के प्रबंध एवं विकास मे उत्पन्न हुई चुनैतियो को ध्यान मे रखते हुए राष्ट्रीय जल निती की पुनरीक्षा एवं इसे अद्यातन किए जाने की आवश्यकता महसुस की जा रही थी. इसके लिए राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद व्दारागठीत कार्यकारी दल ने नई राष्ट्रीय जल नीती का मसौदा तयार कीया इसे राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद व्दारा अप्रैल 2002 मे प्रधानमंत्री की अध्यक्षता मे संपन्न बैठक मे स्वीकार किया गया

मानविय, सामाजिक क्षेत्रीय तथा पर्यावरणीय मुद्दो को ध्यान मे रखते हुए उपभोग योग्य संसाधनी के समन्वित विकास एवं निकासी की दिशा मे नई राष्ट्रीय जल निती 2002 एक सकारात्म्क कदम है. आवश्यकता इस बात की भी है की नदीयो के पानी के उपभोग के मामले मे राज्यो के अपने अपने हितो को त्यागकर समग्र राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य समन्वयवादी दृष्टीकोन अपनाया जाता है भौगोलिक एवं वातावरणीय विभिन्नता ओ वाले देश भारत मे जल स्त्रोतों का प्रबंधन अति संवेदनशिल तथा जटिलमुद्दा है. इसे प्रभावी ढंगा से कार्यान्वित करने के लिए एक समन्वित नीती अपनाए जाने की जरूरत है. जो सर्वसहमती पर आधारीत हो

औद्योगिक विकास तथा शहरो के बढतें आकार ने प्राकृतिक जलस्त्रोतो को खतरनाक स्थिती तक प्रदुषित कर दिया है नगर निकायो ने बढती आबादी के सुख सुविधा तथा आवासोय सुविधा तो उपलब्ध कराई किंतु किसी भी स्तर पर इस बात को प्रयास नही किया कि इन शहरो के गंदो पानी का निस्तारण कैसे हो इसके निस्तारण की सबसे सस्ती विधी के रूप मे शहरो के नालो के नदियो - झिलो- तालाबो मे छोडा गया. इन शहरी क्षत्रो मे स्थापित औद्योगिक इकाईयाँ भी इस कार्य मे पीछे नही रही उन्होने भी अपने गंदे पानी, जिसमे खतरनाक जहरीले रसायन तक मिले होते है. इन्ही नालो के जरिए नदीयो - झिलो - तालाबो मे छोडा.चीन, मिल तापिय विद्युत घर, बडे बडे कारखानो ने नदिया के स्वच्छ् पाणी को प्रयुक्त् करके गंदा पानी इन्ही नदियो के हवाले किया जल अधिनियम 1974 तथा पर्यावरण अधिनियम 1985 के अस्तित्व मे होने के बावजुद जलस्त्रोतो का प्रदुषण बढ रहा है गंगा कार्य योजना तथा यमुना कार्य योजना पर करोडो रूपयो खर्च कर दिए जाने के बावजुद इन नदियो के जल गुणवत्ता मे कोई सकारात्मक

सुधार नही आया है. अनुपचारित गंदा पानी अभी भी इन नदियो मे गिर रहा है. इससे गंभीर समस्या इनकी सहाय्यक नदियो मे बढ रहे प्रदुषण की है. जलस्त्रोतो के प्रबंधन की समग्र कार्यनिती पर प्रदुषण से जुडे मुद्दे पर विचार किया जाना चाहिऐ.

वर्षाधीन क्षेत्रो मे भुमि को नमी को बचाए रखने मे जल संपन्नता की कारगर भुमिका होती है अभी इस कार्य की भुमी विकास के तच के रूपमे देखा जाता रहा है लेकिन अब आवश्यकता है कि इसे जलस्त्रोतो के समग्र विकार एवं प्रबंधन को दृष्टी से देखा जाए.

**उद्दीष्टे :-**

1) नई पाईप लाईन डालकर वैकल्पिय स्त्रोतो से क्षेत्रीय योजनाए मुहैया कराना.

2) पुरानी पड गई योजनाओ वाली बास्तीयो मे नयी योजनाओ की पुरक व्यवस्था करना.

3) वर्षा के जल का अधितम संग्रहण एवं सरंक्षण किया जाना इस दिशा मे अच्छे परिणाम दे सकता है.

4) कृषी मे प्रयुक्त होने वाले किटनाशके, रासायनिक उर्वरको आदि के प्रयोग के नियंत्रीत किया जाना अत्यावश्यक है.

5) तालाबो आदि के चारो और पक्के घाट बनाए जाने चाहिऐ.

6) घरेलु कार्यो मे भी जल के आवश्यकता से अधिक उपयोग को नियंत्रीत किए जाने की आवश्यकता है.

7) जल संकट के निवारण मे स्वयंसेवी संस्थाओ, संचार तथा प्रसार माध्यामो का विशेष हो योगदान होना जरूरी है.

8) वनो की अंधाधुंद काटाई को हर हालत मे रोका जाना चाहिए जिससे भुमिगत जल का स्तर् को तेजी से घटने से रोका जाना संभव हो सकेगा.

**निष्कर्ष :-**

जल की वास्तविकता को समझते हुए इसका उपयोग एक किमती वस्तु के रूप किफायत के साथ किया जाना चाहिये. प्रत्येक व्यक्ती - संस्थान - उद्योगपती - नितीकार को यह समझ लेना चाहिये कि यदी जल संग्रहण को अपनाकर वर्षो के पानी के इस्तामाल को प्रमुखता प्रदान न की गई तो लगातार अतिदोहन भुमिगत जलस्त्रोतो अंतत: सुख जाएगें और भयंकर सुख की मार सबको - कृषक उद्योगपति, व्यापारी, उपमोक्ता सभी समान रूप से सहन करनी पडेगी. इसो प्रकार यदी शहर और उद्योग प्राकृतिक जलस्त्रोतो को आँखो पर पट्टी बाँधकर प्रदुषित करते रहे तो अतंत: पीने के लिए जहरीले रसायन ही शेष बचेंगे. भारतीय अर्थव्यवस्था की कृषी पर निमयता को देखते हुए जलस्त्रोतो के न्यायोचित प्रबंधन की एसी निती अपनाए जाने की आवश्यकता है जो वर्षो के पानी से संग्रहन एवं उपयोग पर आधारीत हो और जिसये भुमिगत जलस्त्रोतो को संकटकाल के लिए सुरक्षित रखा जाए ज्ञान ही नही जलसंग्रहण एवं पुर्नभरण के लिए यदी लोगोने वैयक्तिक स्तर् पर उदासीनता दिखाई तथा स्वार्थी खैय्या अपनाया तो वह दिन दूर नही जब लोग पानी की एक एक बुंद के लिए तरसेंगे.यदी हमने जल संग्रहन के प्रति उदासीनता दिखाई तो देश को जलसंकट क महाप्रलय के दिन देखने पड सकते है.इसके लिए सरकारका मुँह ताकने से अच्छा है लोग खुद आगे आएँ.

**संदर्भ ग्रंथ सुची**

1. जलसंरक्षण समय एवं समाधान :- पी एन नाटाणी, बुक एनक्लेव जयपुर भारत योजना जुन 2006

2. महाराष्ट्रातील जलसंपदा -प्रा.डॉ.एस.व्ही. ढमढरे ,डायमंड पब्लिकेशन पुणे